झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022– 476

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.05.2022

विषयः– राशन कार्डधारियों को कम राशन दिये जाने संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–13.05.2022 को राज्य के राशन कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिये जाने एवं पूरे अनाज का उठाव दर्शाये जाने से संबंधित समाचार प्रकाशित हुई है। उक्त प्रकाशित समाचार में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा भी इस प्रकार की शिकायतें मिलने की बात को स्वीकार किये जाने का भी उल्लेख है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार के कतरन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(14)

हिन्दुस्तान
दिनांक :— 13 मई 2022

झारखंड: अनाज उठाव पूरा पर वितरण अधूरा

झारखंड में राशन कार्डधारियों को पूरे अनाज उठाव की पर्ची तो मिल रही है, लेकिन उन्हें अनाज कम मिल रहा है। हालांकि जितना अनाज दिया जा रहा है उतने की ही राशि ली जा रही है। चावल, गेहूं, नमक तो मिल रहा है, लेकिन केरोसिन तेल निर्धारित कोटे से कम दिया जा रहा है। राज्य के खाद्य व उपभोक्ता मामले के मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने भी माना कि समस्या है और इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। राशन कार्ड होल्डर और डीलर की मीटिंग बुलाकर और उन्हें जागरूक कर इसमें सुधार किया जाएगा। झारखंड में प्रति राशन कार्डधारियों को अनाज निर्धारित मात्रा से दो से तीन किलो कम मिल रहा है। जिन्हें 30-35 किलो अनाज मिलना होता है उन्हें इसमें 28-32 किलो ही अनाज मिल पा रहा है। डीलर कम अनाज मिलने की बात कर राशन कार्डधारियों से यह कटौती करते हैं।

डीलरों की समस्या

कटौती-घटतौली पर राशन डीलरों/कोटेदारों की अपनी सफाई है। गोदाम से अनाज बोरियों के हिसाब से मिलता है। बोरियों में चार-पांच कम किलो अनाज कम निकलता है। ऐसे में कटौती मजबूरी है। भाड़ा भी बड़ा कारण है। सरकार के स्तर पर तीन-चार माह तक उनका कमीशन लटका रहता है और उन्हें अपनी जमा-पूंजी लगाकर अनाज का उठान करना पड़ता है।